



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 149]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 16, 2016/वैशाख 26, 1938

No. 149]

NEW DELHI MONDAY, MAY 16, 2016/VAISAKHA 26, 1938

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 2016

सं. 9/2015-2020

विषय:— निर्यातकों द्वारा ईडीआई सृजित पोतलदान बिलों में वाई अंकित करने को एमईआईएस लाभ का दावा करने हेतु आशय की घोषणा के रूप में माना जाएगा।

फा. सं. 01/61/180/179/ए एम 16/पी सी-3(भाग):—विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक, 2015-20 के पैरा 3.14 (क) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:—

मौजूदा पैराग्राफ

पैराग्राफ 3.14: ई—कामर्स का प्रयोग करने वाले कूरियर अथवा विदेशी डाकघरों के माध्यम से माल के निर्यात सहित एमईआईएस के तहत प्रतिफलों का दावा करने के लिए पोतलदान बिलों पर आशय की घोषणा

(क) पोतलदान बिलों की सभी श्रेणियों के तहत निर्यात पोतलदानों को एमईआईएस के तहत प्रतिफलों का दावा करने के लिए पात्र बनाने के लिए पोतलदान बिलों पर निम्नलिखित घोषणा आवश्यक होगी:—“हम भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात संबंधी स्कीम (एमईआईएस) के तहत प्रतिफलों का दावा करना चाहते हैं।” ऐसी घोषणा विदेश व्यापार नीति के अध्याय-4 (शुल्क वापसी सहित) अध्याय-5 अथवा अध्याय-6 की किसी भी स्कीम के तहत निर्यात पोतलदानों के लिए भी आवश्यक होगी। पोतलदान बिलों (मुक्त पोतलदान बिलों के अलावा) के मामले में आशय की ऐसी घोषणा 1 जून, 2015 से अनिवार्य होगी।

संशोधित पैराग्राफ:

पैराग्राफ 3-14: ई—कामर्स का प्रयोग करने वाले कूरियर अथवा विदेशी डाकघरों के माध्यम से माल के निर्यात सहित एमईआईएस के तहत प्रतिफलों का दावा करने के लिए ईडीआई और गैर-ईडीआई पोतलदानों पर आशय की घोषणा की प्रक्रिया:—

(क) (i) **ईडीआई पोतलदान बिल:** पोतलदान बिलों के “प्रतिफल” कालम में प्रत्येक मद के सामने “वाई” (हां के लिए) अंकित करना/सही का निशान लगाना, जो अनिवार्य है, इस स्कीम के तहत प्रतिफलों का दावा करने हेतु आशय की घोषणा करने के लिए पर्याप्त होगा। यदि निर्यातक विदेश व्यापार नीति के अध्याय-3 के तहत प्रतिफल के लाभ का दावा नहीं करना चाहता है तो निर्यातक “एन” (नहीं के लिए) का निशान लगाएगा। विदेश व्यापार नीति के अध्याय-4 (शुल्क वापसी सहित), अध्याय-5 या अध्याय-6 की स्कीमों में से किसी भी स्कीम के तहत निर्यात खेप के लिए भी इसी तरह अंकित करना/निशान लगाना अपेक्षित होगा।

(ii) **गैर-ईडीआई पोतलदान बिल:** गैर-ईडीआई पोतलदान बिलों के मामले में निर्यात पोतलदानों के लिए एमईआईएस के तहत प्रतिफल का दावा करने हेतु पात्रता के लिए पोतलदान बिलों पर निम्नलिखित घोषणा की आवश्यकता होगी: "हम भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात संबंधी स्कीम (एमईआईएस) के तहत प्रतिफलों का दावा करना चाहते हैं।" इस घोषणा की आवश्यकता विदेश व्यापार नीति के अध्याय-4 (शुल्क वापसी सहित), अध्याय-5 या अध्याय-6 की स्कीम के तहत भेजे जाने वाले निर्यात खेपों के लिए भी होगी।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: प्रक्रिया पुस्तक, 2015-20 के पैरा 3.14 (क) में ईडीआई के लिए आशय की घोषणा संबंधी प्रक्रिया को आसान कर दिया गया है। पूर्व की सार्वजनिक सूचना सं० 47, दिनांक 08 दिसम्बर, 2015 के अनुसरण में सही का निशान लगाने को ईडीआई पोतलदान बिलों के मामले में आशय की घोषणा माना जाएगा। ईडीआई पोतलदान बिलों में उचित सही के स्थानों पर सही का निशान लगाना अनिवार्य है।

अनूप वधावन, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 16th May, 2016

No. 09/2015—2020

Subject: Marking of Y in the EDI generated Shipping Bills by Exporters would be treated as declaration of intent to claim MEIS benefit

F. No. 01/61/180/179/AM16/PC-3/(Pt).—In exercise of powers conferred under paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy 2015-20, Director General of Foreign Trade, hereby makes the following amendments in Paragraph 3.14(a) of the Handbook of Procedures 2015-20:

Existing Paragraph

Paragraph 3.14: Declaration of Intent on shipping bills for claiming rewards under MEIS including export of goods through courier or foreign post offices using e-Commerce

(a) Export shipments filed under all categories of the Shipping Bills would need the following declaration on the Shipping Bills in order to be eligible for claiming rewards under MEIS: **"We intend to claim rewards under Merchandise Exports From India Scheme (MEIS)".** Such declaration shall be required even for export shipments under any of the schemes of Chapter 4 (including drawback), Chapter 5 or Chapter 6 of FTP. In the case of shipping bills (other than free shipping bills), such declaration of intent shall be mandatory with effect from 1st June, 2015.

Amended Paragraph:

Paragraph 3.14 : Procedure for Declaration of Intent on EDI and Non EDI shipping bills for claiming rewards under MEIS including export of goods through courier or foreign post offices using e-Commerce

(a) (i) EDI Shipping Bills: Marking/ticking of "Y" (for Yes) in "Reward" column of shipping bills against each item, which is mandatory, would be sufficient to declare intent to claim rewards under the scheme. In case the exporter does not intend to claim the benefit of reward under Chapter 3 of FTP exporter shall tick "N" (for No). Such marking/ticking shall be required even for export shipments under any of the schemes of Chapter 4 (including drawback), Chapter 5 or Chapter 6 of FTP

(ii) Non-EDI Shipping Bills: In the case of non-EDI Shipping Bills, Export shipments would need the following declaration on the Shipping Bills in order to be eligible for claiming rewards under MEIS: **"We intend to claim rewards under Merchandise Exports From India Scheme (MEIS)".** Such

declaration shall be required even for export shipments under any of the schemes of Chapter 4 (including drawback), Chapter 5 or Chapter 6 of FTP.

Effect of this Public Notice: The procedure for declaration of intent in Paragraph 3.14(a) of the Handbook of Procedures 2015-20 for EDI is simplified. The marking of tick in pursuance of the earlier Public Notice No. 47, dated 8th December 2015 shall be treated as declaration of intent in case of EDI shipping bills. The marking of tick in the appropriate tick boxes are mandatory in EDI shipping bills.

ANUP WADHAWAN, Director General of Foreign Trade